बोलीविया की विख्यात ''डैथ रोड'' अब वन्य जीवों के लिए स्वर्ग बन गई है। बेहद संकड़ी और खतरनाक यह सड़क एक समय ला पाज़ से उत्तर सैन्ट्रल बोलीविया के युगास क्षेत्र जाने का एक मात्र रास्ता था और इस पर हर साल 300 से ज्यादा जानें जाती थीं। तथापि, वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन सोसायटी (डब्ल्यु.सी.एस.) के शोध के अनुसार, 2007 में जब से नई और ज्यादा सुरक्षित सड़क बनी है तब से इस सड़क पर ट्रैफिक 90 प्रतिशत तक कम हो गया है जिसके परिणामस्वरुप वन्य जीवन यहाँ फल-फूल रहा है। वैज्ञानिकों ने 2016 में इस 12 किलोमीटर लम्बी सड़क पर तथा, समीपवर्ती कोटापाटा नैशनल पार्क और नैचुरल इंटीग्रेटेड मैनेजमैंट एरिया में कैमरा ट्रैप लगाए, जिनमें ड्वॉर्फ ब्रॉकैट डियर, माउन्टेन पाका, ऑनसिला कैट और एण्डिअन बिअर देखे गए। एण्डिअन बिअर व ड्वॉर्फ ब्रॉकैट डियर की फुटेज देखकर वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि ये दोनों ही शर्मीले जानवर हैं और उन जगहों से दूर रहते हैं जहां इंसानी गतिविधि हो। डब्ल्यु. सी. एस. के साइन्टिफिक रिसर्च कोऑर्डिनेटर तथा शोध के मुख्य लेखक ग्वीडो आयला ने बताया कि, कैमरों के डेटा से पता चलता है कि वन्य जीव इस क्षेत्र में लौट आएं हैं, क्योंकि यहां ट्रैफिक बहुत कम हो गया है और इंसान भी ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं। आयला ने कहा, जब ''डैथ रोड'' का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था तब ध्वनि प्रदूषण, सड़क हादसे और पालतू जानवरों का व्यापार वन्य जीवों के लिए प्रमुख खतरे थे। शोध में शामिल मारिया विस्कारा ने कहा, जब इस सड़क का इस्तेमाल हो रहा था तब यहां का वन्यजीवन वाहनों से पैदा होने वाले ध्वनि प्रदूषण और धूल से बहुत ज्यादा प्रभावित था। आयला ने कहा, अब ये सब खतरे बहुत कम हो गए हैं तो वन्यजीवों की दशा भी सुधरी है, अब ना तो जानवरों के सड़क हादसे में मरने की खबरें ज्यादा आती हैं ना ही पालतू बनाने के लिए जानवर पकड़ने की। वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा कोका की खेती के लिए आग लगाकर जंगल नष्ट करने से है। कोका की पत्तियों का दवाओं में इस्तेमाल होता है और इससे ही कोकीन बनाई जाती है। इसमें भारी मुनाफा है और इसकी खेती के लिए जंगल में आग लगाकर जमीन साफ की जा रही है।

खुद का बचाव करने दिल्ली पहुंचे धारीवाल, जोशी और राठौड़

हालांकि पार्टी आलाकमान सहित प्रमुख नेता दिल्ली से बाहर हैं, ऐसे में अभी किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हो पाई है

जयपुर, 12 अक्टूबर (का.प्र.)। राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन और पर्यवेक्षक मलिकार्जुन खड़गे की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर 25 सितंबर को बुलाई गई विधायक दल की बैठक के समानांतर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के घर बुलाई गई विधायक दल की बैठक जिसमें पार्टी आलाकमान के खिलाफ भाषण दिए जाने की वजह से मिले कारण बताओ नोटिस का जवाब देने मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि बुधवार को ये नेता दिल्ली में रहे लेकिन आलाकमान के साथ इनकी कोई मुलाकात नहीं हो पाई।

इधर महेश जोशी के कारण बताओ नोटिस पर भेजे गए जवाब तथा उनकी ओर से खुद को पार्टी का अनुशासित सिपाही बताए जाने पर कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने निशाना साधते हुए कहा है कि ''लेकिन फिर स्वयं क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री निवास विधायक दल की मीटिंग में ? खुद इस्तीफ़ा देने क्यों गए विधानसभा अध्यक्ष के निवास? वो स्वयं अगर मीटिंग में जाते तो अन्य विधायक भी प्रेरणा लेते उनसे आख़िरकार मुख्य सचेतक है पार्टी के?

- **प्रभारी अजय माकन के खिलाफ यह नेता खुलकर बयानबाजी कर चुके हैं, अतः इन तीनों की माकन से मुलाकात संभव नहीं लगती।**

तीनों नेताओं पर समानांतर विधायक दल की बैठक बुलाए जाने का आरोप हैं। शांति धारीवाल ने जहां विधायक दल की समानान्तर बैठक का इंतजाम अपने निवास पर किया, वहीं मुख्य सचेतक होने के नाते महेश जोशी ने विधायकों को फोन करके धारीवाल के निवास पर आने को कहा। वहीं बस बुलाने के साथ ही बैठक की कुछ व्यवस्थाएं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने की और वे विधायक नहीं होने के बावजूद भी पूरी बैठक में मौजूद रहे। इतना ही नहीं धारीवाल ने इस बैठक में आलाकमान के खिलाफ भाषण भी दिया जिसका वीडियो वायरल हुआ।

इन तीनों को प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे की रिपोर्ट के आधार पर अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर की ओर से कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसका जवाब 10 दिन में देना था।

यहां एक और मजेदार बात यह भी रही कि एक ओर तो समानांतर बैठक बुलाई गई और उसमें भाषण दिए गए। वहीं बैठक के बाद सभी विधायकों को एक बस में ले जाकर ले जाकर विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) डॉ. सी.पी. जोशी के पास इस्तीफे दिलवाए गए और बाद में प्रभारी अजय माकन के खिलाफ खुलकर बयान भी दिए गए।

धारीवाल और राठौड़ ने तो तय समय पर जवाब दे दिया था, लेकिन महेश जोशी का कहना था कि उन्हें नोटिस देरी से मिला है, इसलिए उन्होंने तय समय 6 अक्टूबर के 5 दिन बाद अपना जवाब दिया है।

जैसे ही तीनों नेताओं ने जवाब देने में अगले दिन ही धारीवाल, जोशी और राठौड़ दिल्ली चले गए। बताया जाता है कि कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बावजूद वे खुद अपने स्तर पर पार्टी आलाकमान और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं।

अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर का कहना है कि पार्टी के राजस्थान प्रभारी और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इन सभी के जवाब का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद क्या कार्यवाही होती है, इस पर निर्णय होगा। बताया जाता है कि अभी सोनिया गांधी और प्रियंका शिमला में हैं।

पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और राजस्थान में पर्यवेक्षक बनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी होने की वजह से वे चुनावी दौरे पर हैं और वे अलग-अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं।

इसलिए इन तीनों की मुलाकात इन नेताओं से होना फिलहाल संभव नजर नहीं आता, लेकिन यह तीनों नेता अनुशासन समिति के सदस्यों से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं। वही प्रभारी महासचिव अजय माकन से मिलने की जहां तक बात है तो इन नेताओं ने अजय माकन के खिलाफ खुलकर सार्वजनिक बयानबाजी की थी तो माकन से इनकी मुलाकात संभव नहीं लगती। इन तीनों नेताओं पर पार्टी कार्यवाही करती है या इन्हें माफी मिलती है, यह 19 अक्टूबर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि तब तक पार्टी के तमाम नेता अध्यक्ष पद के चुनाव में व्यस्त रहने वाले हैं।

सऊदी अरब का झुकाव रूस की ओर बढ़ता देख अमेरिका आशंकित हुआ

अमेरिका ने ऐलान किया है कि, राष्ट्रपति जो बाइडन सऊदी अरब के साथ रिश्तों की समीक्षा करेंगे

- **सऊदी अरब सहित ओपेक संगठन में शामिल 13 देशों और रूस के नेतृत्व वाले उसके 10 सहयोगी देशों ने बीते सप्ताह एक ऐसा फैसला लिया था, जिससे वाइट हाउस का पारा बढ़ गया था।**
- **दरअसल, इन देशों ने फैसला लिया था कि, नवंबर से वे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कटौती करेंगे।**

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बीते कुछ सालों में अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन अब दोनों के बीच दरार आती दिख रही है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि, राष्ट्रपति जो बाइडन सऊदी अरब के साथ रिश्तों की समीक्षा करेंगे। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के हिस्से सऊदी अरब ने रूस का समर्थन करते हुए उत्पादन में कमी का ऐलान किया था। इसके चलते अमेरिका उससे नाराज हो गया है। ओपेक में शामिल 13 देशों और रूस के नेतृत्व वाले उसके 10 सहयोगी देशों ने बीते सप्ताह अपने एक फैसले से वाइट हाउस का पारा बढ़ा दिया था। दरअसल इन देशों ने फैसला लिया था कि नवंबर से वे तेल के उत्पादन में प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल की कमी करेंगे।

इससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने की आशंका जताई जा रही है। अब अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो बाइडन इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट हैं कि सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों की एक बार समीक्षा करनी होगी। किर्बी ने कहा कि निश्चित तौर पर ओपेक देशों के फैसले के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। सऊदी अरब के रूस के साथ जाने से अमेरिका को करारा झटका लगा है, जो उसे अब तक अपने पाले में मानकर चल रहा था।

जो बाइडन ने इसी साल जुलाई में सऊदी अरब का दौरान किया था। इस दौरान वह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मिले थे। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से बेहतर होने के संकेत इस यात्रा से मिले थे।

अमेरिका की आंतरिक राजनीति के लिहाज से भी यह बाइडन के लिए झटके जैसा है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले महंगाई और बेरोजगारी को लेकर पहले ही विपक्ष की ओर से मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं अमेरिका की नाराजगी के बीच सऊदी अरब ने सफाई भी दी है। ओपेक के फैसले को लेकर सऊदी अरब ने कहा कि हमने तेल मार्केट में स्थिरता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है।

मंगलवार को सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने अल-अरबिया चैनल से बातचीत में कहा था कि यह फैसला पूरी तरह से आर्थिक मामला है। लेकिन सऊदी अरब की यह सफाई भी अमेरिका के गले नहीं उतरी है। इसके बाद भी उसकी ओर से ऐलान किया गया है कि सऊदी अरब के साथ रिश्तों की समीक्षा की जाएगी। इस बीच अमेरिकी सीनेट की विदेश मामलों की समिति के मुखिया बॉब मेनेंडेज ने तो साफ तौर पर कहा कि अमेरिका को सऊदी अरब के साथ सभी सहयोग समाप्त कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के फैसले से पूरी दुनिया की इकॉनमी प्रभावित हो सकती है। उसने यह फैसला लेते हुए रूस की ओर से यूक्रेन पर खूंखार हमले की बात को नजरअंदाज किया है।

धतूरे की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजस्थान में पूर्व में मिलने वाली चारों प्रजातियों के फूल का आंतरिक गला सफेद या गंदला सफेद होता है, लेकिन नई प्रजाति के फूल का गले वाला भाग गुलाबी- जामुनी है। यह प्रजाति जालौर जिले में जाबिया, सुंधामाता, पूरन, राजपुरा, दांतलावास, कटोला की ढाणी, भीनमाल में देखी गई। इस प्रजाति को जैसलमेर शहर में भी उगते देखा गया है।

राजस्थान में इस प्रजाति का धतूरा लगभग 60 सेमी ऊँचाई में बढ़ता देखा गया है, जो कई जगह, खासकर जैसलमेर शहर में तो निरंतर एक सघन पैच अर्थात झुण्ड में दिखाई दिए हैं। इस प्रजाति में फूल 16 से 18 सेंटीमीटर लंबा होता है जो बाहर से सफेद होता है लेकिन अंदर गले में गुलाबी -बैंगनी धब्बा होता है।

यह पौधा मूल रूप से उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको तथा करीबिअन द्वीप का निवासी है। मिस्र में इसकी दवा के लिए खेती की जाती है। प्रथम बार इसे 1833 में भारत में बर्नहार्डी नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इस प्रजाति सहित अब राजस्थान में धतूरे की 5 प्रजातियां ज्ञात हो गई हैं। इस महत्वपूर्ण खोज को हाल ही में अनुसंधान जर्नल ''इंडियन जर्नल ऑफ एनवायरमैंटल साइंस'' ने अपने 26 वें अंक में प्रकाशित किया है।

रसोई गैस कंपनियों को 22 हजार करोड़ रू. का अनुदान दिया केन्द्र सरकार ने

- **सरकार का कहना है कि, बीते दो सालों में ग्लोबल मार्केट में गैस की कीमत में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है, इस अनुदान से उनके घाटे की भरपाई होगी**

नयी दिल्ली 12 अक्टूबर (वार्ता)। सरकार ने पिछले दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले दो वर्षों में एलपीजी की कीमतों में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने के कारण घरेलू स्तर पर रसोई गैस वितरण करने वाली कंपनियों को हुये नुकसान की भरपाई के लिए आज 22 हजार करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी प्रदान कर दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोलियम मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार रसोई गैस वितरण करने वाली सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के लिए यह राशि स्वीकृत की गयी है। इन कंपनियों को यह एक बार ही अनुदान दिया जा रहा है।

यह अनुदान जून 2020 से लेकर जून 2022 तक के लिए है।

बयान में कहा गया है कि इस मंजूरी से इन कंपनियों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और मेक इन इंडिया उत्पादों की खरीद का समर्थन भी होगा।

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को विनियमित कीमतों पर की जाती है।

जून 2020 से जून 2022 तक एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर इस लागत वृद्धि को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। ऐसे में इस अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में सिर्फ 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे इन कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। इन नुकसानों के बावजूद तीनों कंपनियों ने देश में इस आवश्यक खाना पकाने के ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।

बड़े थर्मल पावर प्लान्ट...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

2.8 रुपये प्रति यूनिट मिल रही है, जबकि आई.ओ.सी. तथा अन्य 107 याचिकाकर्ता से डिस्कॉम को 3.6 रुपये प्रति यूनिट का खर्चा करना पड़ता था। नियामक आयोग ने सभी 108 पार्टियों से 3.14 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदने का प्रस्ताव दिया था क्योंकि यह उनकी पूल रेट के तहत वाजिब बताया जा रहा था लेकिन जिस पर सहमति नहीं होने से सभी पार्टियों ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया गया था।

गौर फरमाने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डिस्कॉम द्वारा दी गई दर पर आर्थिक दृष्टि से लाभ तो दूर, उल्टे यह प्रोजेक्ट बंद हो जायेगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वह आर.ई.सी. स्कीम के तहत पवन ऊर्जा में निवेश करने वाली कंपनियों को 2.44 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली बनाने के लिये मुआवजा देगी और सौर ऊर्जा बनाने वाली कंपनियों को 2.24 रुपये प्रति यूनिट की दर पर मुआवजा देगी।

आज सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर ने कहा कि इस रिट याचिका की सुनवाई के दौरान ही सरकार ने अपनी नीति को स्वयं ही बदल लिया है जो कि गलत है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 के तहत रिन्युएबल एनर्जी के तहत निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिये ना कि खत्म करना चाहिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह छुपा रही है कि वह ''ब्राऊन एनर्जी'' यानी प्रदूषण फैलाने वाली थर्मल पावर प्लांट इकाइयों से काफी महंगे दर पर बिजली खरीद रही है, जिसकी पिछले साल पूल रेट 5 रु. से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार को ग्रीन एनर्जी सस्ते दामों पर मिल रही है वहीं यह भी सच है कि 75 प्रतिशत बिजली खर्च थर्मल पावर से बनी बिजली का होता है, उन्होंने कहा नियामक आयोग ने पूल रेट में थर्मल पावर से बनी बिजली की रेट को नहीं जोड़ा है, जो वर्तमान में आर.ई.सी. स्कीम वाले प्रोजेक्ट्स से कहीं ज्यादा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर.ई.सी. प्रोजेक्टों को बंद इसलिये करना चाहती है क्योंकि वह थर्मल पावर प्लांट्स को बंद नहीं करना चाहती और इन थर्मल पावर प्लांट्स से जुड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है।

केरल में दो...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी शामिल थी। जून में पहली बलि के बाद, दंपति ने जब कोई वित्तीय सुधार नहीं देखा और शफी के पास गया और फिर शफी ने उनको दूसरी बलि लेने के लिए तैयार किया।

'नई बोतल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नोबेल पुरस्कार में बताया गया है कि वे तथ्य सुविज्ञ हैं, लेकिन इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने बैंकों के कामकाज के इन पहलुओं का औपचारिक परीक्षण किया है। इनमें से दो अर्थशास्त्रियों ने तो और आगे बढ़कर बैंकिंग के इन पहलुओं को गणित से सूत्रबद्ध भी किया है। उन्होंने खासतौर पर बैंक के निर्बाध संचालन के तथ्य बताए हैं।

बैंकों की उपयोगिता को समझने के लिए किसी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।

एक स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें एक भी बैंक ना हो। ऐसी अद्भूत दुनिया में ना हो। ऐसी अद्भूत दुनिया में पैसे बचाकर रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बचत को जमा कराने की जगह ढूंढनी पड़ेगी।

इसी प्रकार, प्रत्येक प्रोजैक्ट का व्यापारिक प्रतिष्ठान को ऐसे व्यक्ति की पहचान करनी होगी जिसके पास पर्याप्त मात्रा में सरप्लस धन हो और उनके काम आ सके।

बाढ़ राहत के पैसे व सहायता सामग्री आम लोगों तक नहीं पहुंची?

अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है

- **अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि, अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगा कि, उसकी सहायता राशि प्रभावित लोगों तक पहुंची अथवा नहीं।**

इस्लामाबाद, 12 अक्टूबर। पाकिस्तान की एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारी बेइज्जती हुई है। इस बार यह बेइज्जती अमेरिका ने की है। अब इस बार पाकिस्तान अपनी बेइज्जती बाढ़ के लिए अमेरिका के तरफ से दिए गए रुपयों को लेकर करा रहा है। पाकिस्तान पर आरोप है कि वह बाढ़ राहत सामग्री और पैसे प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। अमेरिका द्वारा भेजी गई सहायता राशि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और लूट का निवाला बन रही हैं। अमेरिका ने इस पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगा कि उसकी सहायता राशि प्रभावित लोगों तक पहुंची की नहीं।

पाकिस्तान के लिए जून में आफत बन कर आई बारिश की वजह से भीषण बाढ़ आ गयी। बाढ़ में 1700 से भी अधिक लोग मारे गए। वहीं बाढ़ की वजह से 3.30 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए और देश का लगभग एक तिहाई हिस्सा बाढ़ के पानी से डूब गया। पाकिस्तान के लिए अमेरिका एक बार फिर से मसीहा बन कर खड़ा हुआ और पाकिस्तान को इस संकट से उबरने के लिए राहत सहायता भेजी।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिका ने इस वर्ष पाकिस्तान को बाढ़ राहत और मानवीय सहायता के रूप में लगभग 5.65 करोड़ अमेरिकी डॉलर और खाद्य सुरक्षा सहायता के तौर अतिरिक्त एक करोड़ अमेरिकी डॉलर प्रदान किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र ने बाढ़ को लेकर एक पहल शुरू की थी, जिसके तहत 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटाने का प्रयास किया गया। हालांकि इसमें से केवल 3.85 करोड़ डॉलर की सहायता ही हासिल हो पाई।

मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताने वाले इमाम को वाय प्लस सिक्योरिटी मिली

मोहन भागवत से मुलाकात के बाद से इमाम डॉ. उमर अहमद इलियासी को लगातार धमकियां मिल रही थीं

- **हाल ही में डॉ. इलियासी ने कहा था कि, वो अपने दिए गये बयान पर कायम हैं। उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्र ऋर्ष्षि और राष्ट्रपिता कहा था। डॉ. उमर अहमद इलियासी और मोहन भागवत की मुलाकात 22 सितंबर को दिल्ली में हुई थी।**

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताने वाले ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ डॉ. उमर अहमद इलियासी को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। उन्होंने हाल ही में आर.एस.एस. के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इस दौरान इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताया था। मोहन भागवत से मुलाकात के बाद से डॉ. उमर अहमद इलियासी को लगातार धमकियां मिल रही थीं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें वाई-प्लस सुरक्षा प्रदान की है।

हाल ही में डॉ. इलियासी ने कहा था कि वो अपने दिए बयान पर कायम हैं। उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता कहा था। डॉ.उमर अहमद इलियासी और मोहन भागवत की मुलाकात 22 सितंबर को दिल्ली में हुई थी, तब भागवत उनसे मिलने के लिए कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित मस्जिद पहुंचे थे। इलियासी के बयान की कई मुस्लिम संगठनों ने आलोचना की थी और उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी गई। इलियासी के संगठन में भी बयान के बाद से बवाल मचा।

गौरतलब है कि जब आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत, डॉ.उमर अहमद इलियासी से मुलाकात करने गए थे, तो उनके साथ संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल, राम लाल और इंद्रेश कुमार थे। राम लाल पहले बीजेपी के संगठनात्मक सचिव थे, जबकि कुमार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं। बैठक की जानकारियां शेयर करते हुए अहमद इलियासी के भाई सुहैब इलियासी ने कहा था, ''यह काफी अच्छी बात है कि भागवत हमारे पिता की पुण्यतिथि पर हमारे निमंत्रण पर आए। इससे देश में अच्छा संदेश भी गया है।''

आर.एस.एस. प्रमुख साम्प्रदायिक सौहार्द्र को मजबूत करने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा की थी।

उन्होंने हाल में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीरउद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और कारोबारी सईद शेरवानी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भागवत ने हिंदुओं के लिए काफिर शब्द के इस्तेमाल के मुद्दे को उठाया था और कहा था कि इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है।

वहीं, मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की ओर से मुसलमानों को जिहादी और पाकिस्तानी बताए जाने पर आपत्ति जताई थी। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भागवत को यह भी बताया था कि काफिर शब्द के इस्तेमाल के पीछे मकसद कुछ और है, लेकिन कुछ वर्गों में अब इसे अपशब्द के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने बुद्धिजीवियों की चिंताओं को समझते हुए कहा था कि सभी हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है।

रेलवे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और ग्रुप ''सी'' का अन्य स्टाफ शामिल है। इससे रेलवे पर 1832.09 करोड़ रूपयों का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कोविड-19 के बाद की चुनौतियों के कारण उपजी विपरीत वित्तीय स्थिति के बावजूद यह निर्णय लिया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस (पी.एल.बी.) में काउंट किए गए दिन परिभाषित फार्मूले के आधार पर कार्य दिनों से अधिक हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को कैबिनेट के निर्णयों की ब्रीफ्रिंग के दौरान बताया कि पी.एल.बी. एक इन्सैन्टिव है जो कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोत्साहित करता है।

कश्मीर के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करने की कोशिश की है। इस मुहिम को विफल कर देना चाहिए क्योंकि चाहे कश्मीरी हों या डोगरा, हमारे अधिकारों और पहचान की रक्षा तभी होगी, जब हम एक होकर लड़ें।'' यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भी, जिन्होंने हाल ही अपनी नई पार्टी बनाई है, यह कहते हुए इस कदम की आलोचना की है कि जो लोग इस क्षेत्र के नहीं हैं, उन्हें जम्मू में अपने वोट नहीं देने चाहिए। आज़ाद ने कहा कि ''प्रवासी मजदूर एक सिस्टम के अन्तर्गत अपने-अपने राज्यों से बंद लिफाफों में वोट दे सकते हैं।''

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908